

सतत् विकास लक्ष्य 2023-24 में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया चर्चा में क्यों?

नीतिआयोग द्वारा जारी [सतत् विकास लक्ष्य \(SDG इंडेक्स\) 2023-2024 रिपोर्ट](#) में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

मुख्य बढि

- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार पारस्थितिकी और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाकर 'वकिसति उत्तराखंड' की ओर बढ़ने के लिये प्रतबिद्ध है।
- SDG इंडिया इंडेक्स नीतिआयोग द्वारा वकिसति एक उपकरण है, जो [संयुक्त राष्ट्र द्वारा नरिधारति SDG](#) के प्रतभारत की प्रगतिको मापने और ट्रैक करने के लिये है।
 - यह सूचकांक सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का समर्थन करता है तथा राज्यों को इन लक्ष्यों को अपनी वकिस योजनाओं में एकीकृत करने के लिये प्रोत्साहति करता है।
 - यह नीतिनिर्माताओं के लिये अंतराल की पहचान करने तथा [वर्ष 2030 तक सतत् विकास](#) प्राप्त करने की दशिा में कार्यों को प्राथमकिता देने हेतु एक मानक के रूप में कार्य करता है।
- भारत का समग्र SDG स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया, जो वर्ष 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दखिया है।
 - प्रगतमुख्यतः गरीबी उनमूलन, आर्थिक वकिस और जलवायु कार्रवाई में लक्षति सरकारी हस्तक्षेपों से प्रेरति हुई है।
 - शीर्ष प्रदर्शनकर्तता: केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे, जनिमें से प्रत्येक ने 79 अंक प्राप्त किये।
 - सबसे कम प्रदर्शन: बिहार 57 अंकों के साथ सबसे पीछे रहा, उसके बाद झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
 - अग्रणी राज्य: 32 राज्य और केंद्रशासति प्रदेश (UT) अग्रणी श्रेणी में हैं, जनिमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ तथा उत्तर प्रदेश सहति 10 नए राज्य शामिल हैं।

नीतिआयोग

- भारत में योजना आयोग को वर्ष 2015 में नीतिआयोग द्वारा प्रतस्थापति कर दिया गया, जसिमें 'बॉटम अप' अप्रोच की ओर बदलाव कया गया तथा [सहकारी संघवाद](#) पर जोर दिया गया।
 - नीतिआयोग की संरचना में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासति प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा वशिष आमंत्रति सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामति वशिषज्ञ शामिल हैं।
 - प्रधानमंत्री द्वारा एक वशिषिट अवधि के लिये नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो भारत सरकार के सचवि के पद पर होता है।
- मुख्य उद्देश्य हैं- राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाएँ वकिसति करना, आर्थिक रणनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को शामिल करना, समाज के हाशिये पर आए वर्गों पर ध्यान केंद्रति करना, हतिधारकों और थकि टैकों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहति करना, ज्ञान तथा नवाचार हेतु एक समर्थन प्रणाली बनाना, अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करना एवं सुशासन व सतत् विकास प्रथाओं के लिये एक संसाधन केंद्र बनाए रखना।